मासिक पत्रिका

प्रदेश रुचि

RNI-CHHHIN/2021/82341

सच्ची खबर,पक्की खबर

मूल्य 30/-

● वर्ष-7 ● अंक-04 ● अक्टूबर-2026 ● बालोद (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित ● पृष्ठ-32



किताबों से निकलकर प्रयोगों की दुनिया में पहुंचेंगे बच्चे

बालोद में आकार लेगा विज्ञान का नया संसार



अपराधियों पर कार्रवाई, जनसेवा में भागीदारी बालोद पुलिस की बहुआयामी पहल

कानून-व्यवस्था से लेकर सड़क सुरक्षा, साइबर जागरूकता और नशामुक्ति तक अभियान; रक्तदान, स्वास्थ्य परीक्षण और स्वच्छता के जरिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन



बालोद। अपराधों पर अंकुश लगाने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के साथ बालोद पुलिस सामाजिक सरोकारों के निर्वहन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, साइबर अपराधों से बचाव और नशामुक्ति को लेकर किए जा रहे प्रयास पुलिस की बहुआयामी कार्यशैली को दर्शाते हैं। पुलिस की इन पहलों में जनसहभागिता और जागरूकता को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत 15 प्रकरणों में 15 व्यक्तियों तथा धारा 126 एवं 135(3) के तहत 21 प्रकरणों में 25 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत सात प्रकरण दर्ज कर सात आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा पर जोर

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के अंतर्गत पुरूर थाना क्षेत्र के लगभग 22 किलोमीटर मार्ग का निरीक्षण किया। मड़कोटला घाटी, राजाराव पठार, जगतरा टोल प्लाजा और अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों का जायजा लेकर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मार्ग पर संकेतक, स्टॉपर और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं विकसित करने के साथ मड़कोटला घाटी में सोलर लैंप लगाने का सुझाव भी दिया गया। इस पहल का उद्देश्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाना है।

जनजागरूकता के साथ रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण

दल्लीराजहरा में आयोजित व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से यातायात सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव और नशामुक्ति का संदेश दिया गया। बाइक रैली के जरिए हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग तथा यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सात नागरिकों और आठ पुलिसकर्मियों सहित कुल 15 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि 100 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। लर्निंग लाइसेंस शिविर में 70 लोगों ने लाइसेंस बनवाए। आम नागरिकों को हेलमेट वितरित करने के साथ विद्यार्थियों ने रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।

स्वच्छता और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान

सेवा संकल्प अभियान के तहत पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं साइबर सेल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया। वहीं साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को ओटीपी, पिन और पासवर्ड साझा नहीं करने, संदिग्ध लिंक से बचने तथा साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की समझाइश दी गई। बालोद पुलिस की ये गतिविधियां अपराध नियंत्रण के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और जनसहभागिता के महत्व को भी रेखांकित करती हैं। कानून के प्रभावी पालन, जागरूक नागरिकों की भागीदारी और निरंतर कार्रवाई से ही सुरक्षित, अनुशासित एवं अपराधमुक्त समाज की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

मासिक पत्रिका

प्रदेश रुचि

सच्ची खबर,पक्की खबर

RNI-CHHHIN/2021/82341

अक्टूबर-2026 (मासिक)

●वर्ष-7 ●अंक-05

●पृष्ठ-32

बालोद (छत्तीसगढ़)

से प्रकाशित

मूल्य-30/-

संपादक

संतोष कुमार साहू

सलाहकार संपादक

मोहनदास मानिकपुरी

स्थानीय संपादक

देवेंद्र कुमार साहू

रमन टुवानी

छायाकार

तनवीर आलम

विशेष सहयोग

नरेश श्रीवास्तव

स्वामी,प्रकाशक, मुद्रक संतोष कुमार साहू द्वारा मंयक आफसेट,कंकाली तालाब के सामने,जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) से मुद्रित कर हाऊस नं.192/2, स्टेशन रोड,पररास,जिला-बालोद (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

संपादक

*संतोष कुमार साहू

*पी.आर.बी.एक्ट के तहत समस्त समाचार/लेखों के चयन के लिए जिम्मेदार

मोबाइल- 9893162815,7000553221

E-mail- pradeshruchi@gmail.com

*(सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र बालोद होगा)

पेज-3



किताबों से निकलकर प्रयोगों की दुनिया में पहुंचेंगे बच्चे

बालोद में आकार लेगा विज्ञान का नया संसार

7



223 करोड़ की सड़क पर एक साल में ही गड्ढे..

9



साय के सपनों को बालोद में मिल रही रफ्तार, कलेक्टर दिव्या मिश्रा..

30 साल बाद बैसाखी का सहारा छूटा, जागेश्वर ने अपने पैरों पर चलकर फिर नए जीवन की उम्मीद पाई-पेज 11

12



डिजिटल क्रॉप सर्वे में बालोद ने रचा सफलता का नया अध्याय

14



स्कूलों की चौखट तक पहुंच रहे जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे, शिक्षा ..

मतदाता सूची से संसद तक सियासी संग्राम कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने-सामने

संपादक की कलम से

सच क्या है और झूठ क्या है,देश जानता है....



संतोष कुमार साहू

राजनीति में कई बार किसी का पक्ष लेने के लिए, मजबूरी में किसी के साथ खड़े होने के लिए,देश को यह बताने के लिए हम सच के साथ खड़े हैं पूरा सच नहीं कहा जाता है,आधा सच कहा जाता है और इस तरह कहा जाता है कि लोगों को लगे कि यह सच है,यही पूरा सच है और देश के लोगों को हमारे सच पर ही यकीन करना चाहिए। देश के लोगों को हम जो कह रहे हैं,उसी पर यकीन करना चाहिए।लेकिन आधे सच की पोल जल्द ही खुल जाती है,सोशल मीडिया के जमाने में कोई इधर आधा सच कहता है और उसके कुछ मिनट बाद ही पूरा सच देश के लोगों के सामने आ जाता है और देश को पता चल जाता है कोई आधा सच कह रहा है तो पूरा सच क्या है।आधा सच अक्सर अपने राजनीतिक फायदे और विरोधी को नुकसान पहुंचान के इरादे से ही कहा जाता है लेकिन कई बार उससे कहने वाले को राजनीतिक फायदा तो नहीं होता है,उल्टे राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाता है कि यह आदमी झूठ कहता है और जब भी झूठ कहता है,पकड़ा भी जाता है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसे ही नेता हैं,जब भी आधा सच कहते हैं तो पूरा सच देश की जनता के सामने आ जाता है और उनको राजनीतिक रूप से फायदा होने की जगह नुकसान होता है कि वह आधा सच क्यों कहते हैं,जबकि उनको मालूम है कि कुछ ही देर में उनके आधे सच के जवाब में पूरा सच देश के सामने आ आएगा।राहुल गांधी को कोई जरूरत नहीं थी काकरोच जनता पार्टी के नेताओं के जंतर मंतर में तिरंगा फहराने पर यह कहने की कि जंतर मंतर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए .युवाओं को जेल में डालना कायर-तापूर्ण कदम है।यह सच है कि कहीं पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है।लेकिन तिरंगा कहां फहराया जा रहा है और क्यों फहराया जा रहा है,यह भी विचार का विषय होना चाहिए।जैसे काकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास व आशुतोष रांका को मालूम था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन अब नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसे विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से निकाल दिया है यानी अब वहां पर किसी भी तरह का प्रदर्शन गैरकानूनी है। जंतर मंतर में प्रदर्शन गैरकानूनी है मालूम होने के बाद काकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर तिरंगा फहराकर प्रदर्शन किया। यानी वहां बिना अनुमति के गए और तिरंगा फहराया। वहां बिना अनुमति के जाना ही पहला अपराध था,इस अपराध की सजा से बचने के लिए दोनों नेता कहते हैं कि हम तो जंतर मंतर तिरंगा फहराने गए थे।वह मानते हैं कि तिरंगा फहराने के कारण उनके अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा।ऐसा हुआ उन्होंने जंतर मंतर में बिना अनुमति के गए और इसी अपराध के कारण उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने भी उनके इस अपराध को गंभीरता से लिया और उनको जमानत पर रिहा करने की जगह पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज कर एक तरह से मान लिया कि दोनों ने जानबू-झकर अपराध किया है इसलिए दोनों को सजा मिलनी चाहिए। दोनों को पुलिस ने इससे पहले राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने पर गिरफ्तार किया था और मजिस्ट्रेट का सामने पेश किया गया था तो यहां उनको एक साथ तक शांति बनाए रखने के नाम पर बांड भरवाकर रिहा किया गया था।यानी दोनों ने अदालत से वादा किया था कि वह रिहा होने के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बांड की शर्त भंग होती है लेकिन उन्होंने एक निजी परिसर से होकर जंतर मंतर में घुसकर वही किया जो अदालत में नहीं करने का वादा किया था। यानी सौरव दास व आशुतोष रांका ने दो अपराध किए एक तो भरे गए बांड के खिलाफ काम किया, दूसरा बिना अनुमति निजी परिसर से होकर जंतर मंतर में गए और झंडा फहराया। उनको झंडा फहराने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको गिरफ्तार निजी परिसर में बिना अनुमति जाने और जंतर मंतर में घुसने पर किया गया है। चाहे काकरोच जनता पार्टी हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी वह आधा सच कह रहे हैं कि तिरंगा फहराने कोई अपराध नहीं है और दोनों को तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार किया गया है।अब तक राहुल गांधी व कांग्रेस काकरोच जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए थे,वह अलग प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस अलग इंडी गठबंधन के साथ प्रदर्शन कर रही थी। दोनों के बीच होड़ लगी हुई थी कौन ज्ञानेश कुमार का ज्यादा विरोध कर सकता है।एक दिन कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती थी तो एक दिन काकरोच जनता पार्टी वाले विरोध प्रदर्शन करते थे।पहली बार राहुल गांधी काजपा के नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बयान दिया है तो इसकी एक वजह तो यही हो सकती है कि वह चाहते हैं कि देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वह बिखरा हुआ न लगे, ऐसा लगे कि विपक्ष के सब नेता एकजुट हैं और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किताबों से निकलकर प्रयोगों की दुनिया में पहुंचेंगे बच्चे, बालोद में आकार लेगा विज्ञान का नया संसार

डौंडी ब्लॉक के पथराटोला में 5 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित साइंस सेंटर बनेगा विज्ञान, नवाचार और आधुनिक तकनीक की सीख का केंद्र; प्लेनेटेरियम से एआई-रोबोटिक्स तक नौ इंटरैक्टिव जोन होंगे आकर्षण का केंद्र



बालोद ⏭ (प्रदेश रुचि)

विज्ञान केवल किताबों के पन्नों पर लिखे सिद्धांतों का विषय नहीं, बल्कि जिज्ञासा, कल्पना, प्रयोग और अनुभव से होकर गुजरने वाली वह यात्रा है, जो मनुष्य को अज्ञात के रहस्यों तक पहुंचाती है। जब किसी बच्चे को किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ने के साथ उसे अपनी आंखों से देखने, अपने हाथों से परखने और उसके पीछे छिपे तर्क को समझने का अवसर मिलता है, तब ज्ञान महज परीक्षा की तैयारी नहीं रह जाता, बल्कि जीवनभर साथ चलने वाली समझ में बदलने लगता है। इसी विचार को धरातल पर उतारने की दिशा में बालोद जिले के डौंडी विकासखंड अंतर्गत पथराटोला में प्रस्तावित 'साइंस सेंटर एंड एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन' जिले की शैक्षणिक संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विज्ञान, नवाचार तथा आधुनिक शिक्षा से जुड़ने की दिशा में प्रस्तावित यह केंद्र बालोद के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सीखने के नए द्वार खोलने की परिकल्पना लेकर आगे बढ़ रहा है। लगभग पांच करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत से विकसित होने वाला यह केंद्र केवल एक भवन या वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे ऐसा अनुभवात्मक शैक्षणिक परिसर बनाने की योजना है, जहां विज्ञान को देखा भी जा सकेगा, समझा भी जा सकेगा और प्रयोगों के माध्यम से अनुभव भी किया जा सकेगा।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी के अनुसार, साइंस सेंटर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगामी आठ से दस दिनों में वर्क ऑर्डर जारी किए जाने की संभावना है। निर्माण कार्य की निर्धारित अवधि छह माह रखी गई है। इस समय-सीमा के आधार पर मार्च 2027 तक केंद्र के तैयार होने का अनुमान है। चंद्रवंशी के मुताबिक, यह दुर्ग संभाग का पहला विज्ञान केंद्र होगा, जबकि दंतेवाड़ा और रायपुर के बाद बालोद में प्रदेश का तीसरा ऐसा केंद्र स्थापित होने की बात कही गई है।

विज्ञान को रटने से समझने तक का सफर

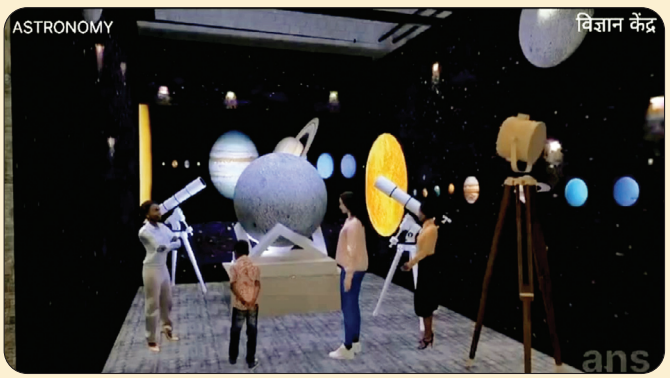
पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान के अनेक सिद्धांत विद्यार्थियों तक पाठ्यपुस्तकों, चित्रों और कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों के माध्यम से पहुंचते हैं। हालांकि, कई बार सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में समझने के अवसर सीमित रह जाते हैं। प्रस्तावित साइंस सेंटर इसी दूरी को कम करने का माध्यम बन सकता है। यहां सीखने की प्रक्रिया केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित न होकर देखने, छूने, प्रयोग करने और परिणामों को समझने पर आधारित होगी।

केंद्र की मूल अवधारणा विद्यार्थियों को विज्ञान के साथ सक्रिय रूप से जोड़ने की है। प्रवेश से लेकर खोज, सहभागिता, अनुभव और समझ तक की प्रक्रिया इस तरह विकसित करने की योजना है कि बच्चे किसी वैज्ञानिक अवधारणा को केवल याद न करें, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले सिद्धांत को भी समझ सकें। इस प्रकार कक्षा में अर्जित ज्ञान को वास्तविक अनुभवों से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बचपन से ही विकसित होती है। आकाश में चमकते तारों से लेकर पृथ्वी की संरचना, मानव शरीर की कार्यप्रणाली, रोबोट की गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारणों तक बच्चों के मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्रयोगों और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से मिलें, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक सहज, रोचक और स्थायी बन सकती है। प्रस्तावित केंद्र इसी शैक्षणिक सोच को व्यवहार में उतारने का प्रयास है।

प्लेनेटेरियम से रोबोटिक्स तक, विज्ञान के नौ संसार

प्रस्तावित साइंस सेंटर की विशेषता यहां विकसित किए जाने वाले नौ इंटरैक्टिव जोन होंगे। इन क्षेत्रों के माध्यम से विज्ञान और तकनीक के विविध आयामों को एक ही परिसर में अनुभव करने की योजना है। इनमें प्लेनेटेरियम, स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी, एआई एवं रोबोटिक्स स्टूडियो, एसटीईएम डिस्कवरी पार्क, ह्यूमन एनाटॉमी गैलरी, आपदा जागरूकता अनुभव क्षेत्र, इमर्सिव हेरिटेज जोन, टाइम एंड हिस्ट्री थिएटर तथा खगोल विज्ञान डिस्कवरी जोन शामिल हैं। प्लेनेटेरियम बच्चों और युवाओं को ब्रह्मांड की विशालता, तारों की दुनिया तथा अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा से परिचित कराने का माध्यम बनेगा। इमर्सिव तकनीक के जरिए खगोलीय घटनाओं और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों को इस तरह प्रस्तुत करने की योजना है कि विद्यार्थी उन्हें केवल कल्पना में न देखें, बल्कि एक विशेष अनुभव के रूप में महसूस कर सकें। स्पेस एक्सप्लो-



रेशन गैलरी में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने की परिकल्पना है। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे अभियानों से जुड़ी जानकारी विद्यार्थियों को देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा अंतरिक्ष अनुसंधान की संभावनाओं से परिचित करा सकती है। इससे विज्ञान की पढ़ाई को देश में हो रहे वास्तविक अनुसंधान और तकनीकी विकास से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

इसी क्रम में एआई एवं रोबोटिक्स स्टूडियो आधुनिक तकनीक की दुनिया से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का शुरुआती अनुभव विद्यार्थियों को भविष्य में तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्रों को समझने में मदद करेगा। वहीं एसटीईएम डिस्कवरी पार्क में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के सिद्धांतों को गतिविधियों तथा प्रयोगों के माध्यम से समझाने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि गणित के सूत्र, भौतिकी के नियम और इंजीनियरिंग के सिद्धांत वास्तविक जीवन में किस तरह उपयोगी साबित होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी गैलरी मानव शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने का अवसर दे सकती है। दूसरी ओर, इमर्सिव हेरिटेज जोन और टाइम एंड हिस्ट्री थिएटर के माध्यम से इतिहास, विरासत और समय के विभिन्न आयामों को अनुभवात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की परिकल्पना है। खगोल विज्ञान डिस्कवरी जोन आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड से संबंधित जिज्ञासाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में सहायक हो सकता है।

इस तरह प्रस्तावित केंद्र में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एक-दूसरे से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के सामने ज्ञान की ऐसी दुनिया प्रस्तुत करने का लक्ष्य है, जिसमें जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी बने।

एआई और रोबोटिक्स के दौर में भविष्य की तैयारी

दुनिया जिस तेजी से तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में शिक्षा और रोजगार के अनेक क्षेत्र इन तकनीकों से प्रभावित होंगे। ऐसे में छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीक से परिचित कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बालोद में प्रस्तावित साइंस सेंटर इस दिशा में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए अवसरों का एक नया माध्यम बन सकता है। यदि केंद्र में नियमित रूप से प्रयोगात्मक गतिविधियां, तकनीकी प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, तो विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से ही विज्ञान तथा तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों को समझने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप आगे की पढ़ाई तथा संभावित करियर विकल्पों को पहचानने में भी सहायता मिल सकती है। इस केंद्र की उपयोगिता केवल विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होगी। शिक्षक, कॉलेज के विद्यार्थी, युवा, परिवार और विज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखने वाले आम नागरिक भी यहां आयोजित गतिविधियों से लाभान्वित हो सकते हैं। शिक्षकों के लिए यह केंद्र शिक्षण की नई विधियों को समझने और कक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का माध्यम बन सकता है।

आपदाओं की समझ और सुरक्षा का व्यावहारिक पाठ

प्रस्तावित केंद्र में बाढ़, भूकंप, आग और रासायनिक आपात स्थितियों से संबंधित सिमुलेशन आधारित अनुभव क्षेत्र विकसित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य लोगों को संभावित आपदाओं की प्रकृति, उनसे जुड़े जोखिमों और सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रति जागरूक करना है। आपदा प्रबंधन की जानकारी केवल पुस्तकों तक सीमित रहने के बजाय यदि उसे परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किए गए सिमुलेशन और प्रदर्शन के माध्यम से समझाया जाए, तो उसका व्यावहारिक महत्व बढ़ सकता है। विशेषकर विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ऐसी गतिविधियां संकट के समय सावधानी, सतर्कता और सुरक्षित व्यवहार की समझ विकसित करने में सहायक हो सकती हैं। इस दृष्टि से साइंस सेंटर का स्वरूप केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने वाले परिसर का नहीं, बल्कि विज्ञान को दैनिक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने वाले मंच का भी हो सकता है।

सालभर सक्रिय रहेगा तो बढ़ेगी उपयोगिता

किसी भी शैक्षणिक केंद्र की वास्तविक सफलता केवल उसके निर्माण और आकर्षक संरचना से तय नहीं होती। उसकी उपयोगिता इस



बात पर निर्भर करती है कि वहां विद्यार्थियों को सीखने के कितने अवसर मिलते हैं और समय के साथ उसकी गतिविधियां कितनी प्रभावी बनी रहती हैं। प्रस्तावित साइंस सेंटर में स्कूल विजिट, लाइव साइंस डेमो, एआई वर्कशॉप, एसटीईएम प्रतियोगिताएं, शिक्षक प्रशिक्षण और मौसमी प्रदर्शनियां आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। यदि इन गतिविधियों को नियमित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप संचालित किया जाता है, तो केंद्र को सालभर सक्रिय रखा जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जा सकते हैं। स्थानीय शिक्षकों और विज्ञान विषय के विशेषज्ञों की सहभागिता से कार्यशालाओं तथा प्रयोगात्मक सत्रों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र में प्रदर्शित तकनीक और उपकरणों का नियमित रखरखाव, प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता तथा समयानुकूल शैक्षणिक सामग्री का समावेश भी आवश्यक होगा। इन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, तो साइंस सेंटर की उपयोगिता केवल शुरुआती आकर्षण तक सीमित रहने के बजाय दीर्घकालीन शैक्षणिक लाभ में बदल सकती है।

बालोद से विज्ञान और नवाचार की नई राह

बालोद जैसे जिले में आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जुड़ा अनुभवात्मक केंद्र स्थापित होने की परिकल्पना स्थानीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नई संभावना प्रस्तुत करती है। अब तक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रदर्शनियों और तकनीकी अनुभवों के लिए विद्यार्थियों को बड़े शहरों या विशेष शैक्षणिक संस्थानों की ओर रुख करना पड़ सकता है। जिले में ऐसा केंद्र विकसित होने से इस दूरी को कम करने में मदद मिल सकती है। इसका लाभ केवल बालोद तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। आसपास के जिलों के शैक्षणिक संस्थान भी इसे अपने विद्यार्थियों के अध्ययन और अनुभवात्मक शिक्षा से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार यह केंद्र भविष्य में शैक्षणिक भ्रमण, विज्ञान आधारित गतिविधियों और नवाचार से जुड़ी पहलों के लिए क्षेत्रीय आकर्षण बन सकता है। हालांकि, प्रस्तावित परियोजना की परिकल्पना जितनी व्यापक है, उसकी सफलता के लिए क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित समय पर निर्माण पूरा करना, गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं विकसित करना, नियमित संचालन सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना इसकी वास्तविक उपलब्धि तय करेंगे।

विकसित भारत की कल्पना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालोद का प्रस्तावित साइंस सेंटर इसी व्यापक सोच को स्थानीय स्तर पर अनुभव में बदलने की संभावना रखता है। यदि यह योजना अपनी परिकल्पना के अनुरूप आकार लेती है, तो पथराटोला का यह परिसर बच्चों के लिए केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि सवाल पूछने, नए विचार गढ़ने और विज्ञान की दुनिया को समझने का ऐसा मंच बन सकता है, जहां आज की जिज्ञासा कल के नवाचार की नींव रखेगी।

"विद्यार्थियों को प्रयोग और अनुभव से सीखने का मिलेगा अवसर"

जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी के अनुसार, प्रस्तावित साइंस सेंटर जिले के विद्यार्थियों और युवाओं को विज्ञान एवं तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें प्रयोग और अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर देना है। एआई, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, एसटीईएम और अन्य आधुनिक तकनीकों से जुड़े इंटरैक्टिव माध्यम विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा विकसित करने में सहायक होंगे। यह केंद्र आने वाले समय में बालोद सहित आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं के लिए एक उपयोगी शैक्षणिक मंच के रूप में विकसित हो सकता है।

सुनील चंद्रवंशी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद

"विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर"

सत्ता का वास्तविक वैभव राजसिंहासन में नहीं, बल्कि जनसेवा के उस भाव में निहित होता है, जो शासन को जनमानस की आकांक्षाओं से जोड़ता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सार्थकता इसी कसौटी पर परखी जा रही है, जहां सुशासन, संवेदनशीलता और विकास की त्रिवेणी से नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर गढ़ने का प्रयास दिखाई देता है। लोकतंत्र की आत्मा जनता के विश्वास में बसती है और इस विश्वास को सुदृढ़ करने का सबसे प्रभावी माध्यम है—सेवा का संकल्प। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्हें जनसामान्य स्नेहपूर्वक 'विष्णु भैया' कहकर संबोधित करता है, के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा जनअपेक्षाओं, लोककल्याण और प्रशासनिक जवाबदेही के व्यापक विमर्श से जुड़ी है। यह यात्रा केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं, बल्कि शासन और समाज के बीच विश्वास का सेतु निर्मित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संपदा और श्रमशील जनमानस से है। यहां विकास का अर्थ केवल सड़कों, भवनों और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि गांवों में समृद्धि, किसानों के जीवन में खुशहाली, युवाओं के लिए अवसर और वंचित वर्गों के जीवन में सम्मान का संचार भी है। जब शासन की प्राथमिकताओं में समाज के अंतिम व्यक्ति का हित स्थान पाता है, तभी विकास की अवधारणा अपने वास्तविक अर्थों में चरितार्थ होती है।



सुशासन की सार्थकता प्रशासनिक पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय, योजनाओं की प्रभावी पहुंच और जनसमस्याओं के संवेदनशील निराकरण में निहित है। सरकार की प्रत्येक पहल का मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए कि उससे आम नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हों तथा किसानों और श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो—ये किसी भी जनोन्मुखी शासन की अनिवार्य कसौटियां हैं।विष्णुदेव साय के नेतृत्व के समक्ष भी यही व्यापक दायित्व है कि विकास की गति प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे। विशेषकर आदिवासी अंचलों, दूरस्थ गांवों और अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सामाजिक न्याय की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है। विकास तभी समावेशी कहलाएगा, जब उसकी रोशनी महानगरों से निकलकर गांव की अंतिम चौखट तक पहुंचेगी।

हालांकि, किसी भी सरकार की वास्तविक उपलब्धियां केवल घोषणाओं अथवा संकल्पों से नहीं, बल्कि उनके धरातलीय परिणामों से निर्धारित होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र जनोन्मुखी बने, योजनाओं की नियमित समीक्षा हो और जवाबदेही की संस्कृति मजबूत की जाए। जनविश्वास बनाए रखने के लिए उपलब्धियों के साथ चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान खोजना भी सुशासन का अनिवार्य अंग है। अंततः, छत्तीसगढ़ का भविष्य केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि शासन, समाज और नागरिकों की साझा सहभागिता से आकार लेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की विकास यात्रा तभी अधिक सार्थक होगी, जब सेवा का संकल्प प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय में प्रतिबिंबित हो और सुशासन का सेतु प्रत्येक नागरिक को अवसर, सम्मान तथा विश्वास से जोड़े।क्योंकि समृद्ध छत्तीसगढ़ की असली पहचान केवल विकास के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में होगी, जो एक किसान के चेहरे पर खिलेगी, उस आशा में होगी, जो एक युवा की आंखों में जागेगी और उस विश्वास में होगी, जो आम नागरिक के मन में अपने शासन के प्रति दृढ़ होगा। यही सेवा की सार्थकता है, यही सुशासन का उद्देश्य और यही संवरते छत्तीसगढ़ की सबसे सुंदर परिकल्पना है।

223 करोड़ की सड़क पर एक साल में ही गड्ढे, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल



कृष्णकांत पवार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कलेक्टर से जांच कराने की बात कही, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखेंगे पत्र

बालोद ⏭ (प्रदेश रुचि)

करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़कें विकास की रफ्तार बढ़ाने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का माध्यम होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग-930 के झलमला-शेरपार मार्ग की मौजूदा स्थिति निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी धन के सदुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। करीब 223 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 37 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण सितंबर 2025 में पूरा हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2026 तक इसके कई हिस्सों में सड़क की ऊपरी परत उखड़ने, गड्ढे बनने और सड़क धंसने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जिला मुख्यालय बालोद से गुजरने वाले लगभग दो किलोमीटर के हिस्से में हर 50 से 100 मीटर पर गड्ढे नजर आने की स्थिति ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है।

ईई ने स्वीकारा, निर्माण में हुई गड़बड़ी

सड़क की बदहाली पर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता (ईई) संतोष गुप्ता ने स्वीकार किया है कि निर्माण के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि सड़क का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त हिस्सों में पेच रिपेयर कराने और सड़क किनारे उगी झाड़ियों की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का दावा है कि अगले

15 से 20 दिनों में मरम्मत पूरी कर सड़क को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा।

हालांकि, ईई ने सड़क की तुलना झलमला से पुरूर तक के मार्ग से किए जाने पर खदानों से निकलने वाले ओवरलोड वाहनों के दबाव को इसकी बदहाली की एक वजह बताया। लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही पहले से ज्ञात होने के बावजूद सड़क की मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था या नहीं, यह जांच का विषय है।

पांच साल की गारंटी, फिर इतनी जल्दी क्यों खराब हुई सड़क?

विभागीय एसडीओ अनिल कुमार छारी के अनुसार, सड़क पांच साल की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में है। इस दौरान सड़क खराब होने पर ठेकेदार को अपने खर्च पर मरम्मत करनी होगी, जिसके लिए अलग से



भुगतान नहीं किया जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क की जांच कर रिपोर्ट उच्च कार्यालय में जमा की जा चुकी है। हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता, अंतिम भुगतान और तकनीकी जांच के निष्कर्षों को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। सवाल यह है कि जब सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी पांच साल तक ठेकेदार की है, तो निर्माण के महज एक साल बाद ही जगह-जगह गड्ढे और धंसाव क्यों सामने आ रहे हैं? क्या निर्माण सामग्री, सड़क की मोटाई और तकनीकी मानकों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन हुआ था? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष तकनीकी जांच से ही मिल सकता है।

कृष्णकांत पवार करेंगे शिकायत, केंद्रीय मंत्री को भी लिखेंगे पत्र

सड़क की बदहाली का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर पहुंचने की तैयारी में है। दिशा समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णकांत पवार ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से जांच कराने की मांग करने की बात कही है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर मामले से अवगत कराने तथा जरूरत पड़ने पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में शिकायत करने की बात कही है। पवार ने ओवरलोड वाहनों को सड़क खराब होने की वजह बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विभाग को पहले से भारी वाहनों की आवाजाही की जानकारी थी, तो निर्माण के समय उसी के अनुरूप सड़क की मजबूती सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ताहीन निर्माण किए जाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। प्रस्तावित शिकायत और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



गड्ढों से दुर्घटना का खतरा, गुणवत्ता जांच की मांग

सड़क पर गड्ढों के कारण वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय गड्ढों का अंदाजा नहीं लगने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। स्थानीय पार्षदों और नागरिकों ने भी सड़क की गुणवत्ता की जांच, क्षतिग्रस्त हिस्सों की स्थायी मरम्मत और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल पेच रिपेयर पर्याप्त नहीं, बल्कि सड़क के समय से पहले खराब होने के वास्तविक कारणों का पता लगाना जरूरी है। अब निगाहें विभाग के 15-20 दिन के आश्वासन और प्रस्तावित शिकायत पर टिकी हैं। सड़क की मरम्मत से तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन 223 करोड़ रुपये की लागत से बने इस मार्ग की गुणवत्ता पर उठे सवालों का जवाब तकनीकी जांच, निर्माण संबंधी अभिलेखों की पड़ताल और जवाबदेही तय होने से ही मिलेगा। आखिर यह मामला केवल गड्ढे भरने का नहीं, बल्कि सरकारी धन की पारदर्शिता, निर्माण की गुणवत्ता और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है।





साय के सपनों को बालोद में मिल रही रफ्तार, कलेक्टर दिव्या मिश्रा बन रहीं बदलाव की सारथी

सुशासन से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता का नया अध्याय, योजनाओं की जमीनी निगरानी, नवाचार और त्वरित समाधान से जनविश्वास मजबूत करने की पहल

बालोद ⏭ (प्रदेश रुचि)

सुशासन की सार्थकता केवल सरकारी योजनाओं की घोषणा, बजट के आवंटन और उपलब्धियों के आंकड़ों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि शासन की संवेद-नशीलता समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है। प्रशासन जब जनसमस्याओं को अपनी प्राथमिकता बनाता है, योजनाओं को कागजी दायरों से निकालकर धरातल पर उतारता है और विकास को जनभागीदारी से जोड़ता है, तभी सुशासन की परिकल्पना साकार होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है, बालोद जिले में उसे धरातल पर प्रभावी स्वरूप देने की दिशा में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की प्रशासनिक सक्रियता उल्लेखनीय दिखाई देती है। जिले में विकास कार्यों की निगरानी, शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, नागरिकों की समस्याओं का निराकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास शासन की प्राथमिकताओं को जनसरोकारों से जोड़ने की पहल हैं। यहां प्रशासन की भूमिका केवल विभागीय कामकाज के संचालन तक सीमित नहीं, बल्कि योजनाओं के परिणामों को आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी केंद्रित नजर आती है।

सुशासन तिहार से मजबूत हुआ शासन और जनता के बीच संवाद

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है। यह विश्वास तब मजबूत होता है, जब नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि उनकी बात सुनने और समाधान तलाशने के लिए प्रशासन स्वयं सक्रिय हो। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुशासन तिहार के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की मांगों और शिकायतों को सुनने, आवेदनों पर कार्रवाई करने तथा समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास किए गए। यह पहल सरकार और जनता के बीच संवाद की दूरी कम करने का माध्यम बनी। योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों तक पहुंच बनाने और प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में ऐसे प्रयासों की



अहम भूमिका है। कलेक्टर की कार्यशैली में योजनाओं की प्रगति के साथ उनके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने पर जोर देना इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

डिजिटल प्रशासन और समयबद्ध समाधान पर जोर

आधुनिक प्रशासन में तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी साधन भी है। बालोद जिले में एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे, फौती-नामांतरण और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा के माध्यम से प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि और राजस्व से जुड़े ये कार्य सीधे किसानों तथा ग्रामीण परिवारों के हितों से संबंधित हैं। ऐसे में इनकी नियमित निगरानी और लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में सक्रियता का महत्व और बढ़ जाता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, तकनीकी बाधाओं को दूर करना और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ही उस बदलाव की बुनियाद है, जिसकी अपेक्षा आम नागरिक शासन से करता है।

महतारी वंदन से पर्यावरण संरक्षण तक जनभागीदारी का विस्तार



विकास की अवधारणा तब अधिक व्यापक हो जाती है, जब उसमें सामाजिक सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व दिया जाए। बालोद जिले में महतारी वंदन वृक्षारोपण पहल के माध्यम से महिलाओं और बेटियों को पौधारोपण अभियान से जोड़ने का प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। इस पहल का महत्व केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व और भावी पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य के निर्माण का संदेश भी देती है। सरकारी अभियान जब जनसहभागिता का रूप लेते हैं, तब उनके परिणाम अधिक स्थायी और व्यापक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

नवाचार के साथ भविष्य की जरूरतों पर नजर

प्रशासनिक कार्यशैली में नवाचार का समावेश किसी जिले के विकास को नई दिशा दे सकता है। जिला प्रशासन परिसर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा की शुरुआत आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का उदाहरण है। वहीं साइबर जागृति अभियान के माध्यम से डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने की पहल बदलते समय की जरूरतों को समझने का संकेत देती है। आज डिजिटल सेवाओं का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक होती जा रही है। ऐसे में जनजागरूकता को प्रशासनिक प्राथमिकताओं में शामिल करना नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

तांदुला जलाशय : जल संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन की नई दिशा

बालोद की पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा और तांदुला जलाशय जैसी महत्वपूर्ण जल संरचनाओं से भी जुड़ी है। जलाशय का संरक्षण, उसके जलग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप जल संसाधनों की सुरक्षा जिले के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।



इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई की इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के सहयोग से जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन तथा कार्ययोजना तैयार करने की पहल उल्लेखनीय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जल संसाधनों का आकलन और संरक्षण की रणनीति तैयार करना भविष्य की जल सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।यह पहल इस विचार को भी मजबूती देती है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए विकास की गति बनाए रखना ही दूरदर्शी प्रशासन की पहचान है।

जवाबदेही से ही साकार होगा सुशासन का संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और

जनकल्याण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन प्राथमिकताओं को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका निर्णायक होती है। बालोद में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की कार्यशैली इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। विभागीय समीक्षा, योजनाओं की मैदानी प्रगति पर नजर, नागरिकों की समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार जैसे प्रयास तभी सार्थक होंगे, जब उनका प्रभाव आमजन के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए प्रशासन की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल स्वीकृत कार्यों की संख्या या व्यय की गई राशि नहीं, बल्कि उन कार्यों से लोगों को मिली राहत, सुविधाओं की उपलब्धता और जीवन स्तर में आया सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए।

बालोद में सुशासन की यह यात्रा प्रशासनिक सक्रियता, तकनीकी नवाचार, जनभागीदारी और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के समन्वय से आगे बढ़ती दिखाई देती है। मुख्यमंत्री के विजन को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब इन प्रयासों की निरंतरता, योजनाओं के परिणामों की प्रभावी निगरानी और जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने की क्षमता ही इस बदलाव को स्थायी स्वरूप प्रदान करेगी।क्योंकि सुशासन का असली अर्थ केवल व्यवस्था चलाना नहीं, बल्कि व्यवस्था के माध्यम से जनजीवन को बेहतर बनाना है। जब प्रशासन संवेदनशीलता को अपना स्वभाव, जवाबदेही को अपना दायित्व और विकास को अपना लक्ष्य बनाता है, तभी शासन का संकल्प जनविश्वास में बदलता है। बालोद में इसी सोच को धरातल पर साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन की सक्रियता एक महत्वपूर्ण कड़ी बन रही है।

30 साल बाद बैसाखी का सहारा छूटा, जागेश्वर ने अपने पैरों पर चलकर फिर नए जीवन की उम्मीद पाई

बालोद ⏭ (प्रदेश रुचि)

कभी बैसाखी के सहारे जिंदगी गुजारने की मजबूरी, कभी पढ़ाई छूट जाने का दर्द, तो कभी दूसरों पर निर्भर रहने की बेबसी। इन मुश्किलों के बीच जब उम्मीद का सहारा मिला, तो आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। किसी ने 30 साल बाद अपने पैरों पर चलने का सुख महसूस किया, तो किसी के चेहरे पर फिर से स्कूल जाने और अपने सपनों को पूरा करने की मुस्कान लौट आई। यह बदलाव केवल कृत्रिम पैर मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है। केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी



योजनाओं और सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जिले में मानवीय संवेदना की ऐसी ही प्रेरक मिसाल सामने आई है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की संवेदनशील पहल की जा रही है, ताकि वे अपनी शारीरिक कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसी कड़ी में आज संयुक्त जिला कार्यालय में जिले के तीन दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर प्रदान किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख और श्री अभिषेक शुक्ला ने दिव्यांगजनों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने उनके अनुभवों को जाना और कृत्रिम पैर मिलने के बाद जीवन में आए बदलावों के बारे में जानकारी ली। अतिथियों ने सभी को शॉल भेंटकर उनके सुखद, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भविष्य की कामना की। डौण्डी विकासखंड के ग्राम धुर्वाटोला निवासी श्री जागेश्वर के जीवन में पिछले 30 वर्षों से एक ऐसी मजबूरी थी, जिसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना दिया था। लगभग तीन दशक पहले जहरीले सांप के काटने के कारण पैर में संक्रमण फैल गया और चिकित्सकों को उनका एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद से बैसाखी ही उनके जीवन का सहारा बन गई थी। बिना किसी सहारे के चलना उनके लिए एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन सेवा संकल्प अभियान के तहत कृत्रिम पैर मिलने से उनके जीवन में नई उम्मीद जाग उठी। कृत्रिम पैर लगाने के बाद चलने का अभ्यास करते हुए जब उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो वर्षों की बेबसी के बीच आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई देने लगी। जागेश्वर के लिए यह केवल कृत्रिम पैर नहीं, बल्कि 30 वर्षों से अधूरे रह गए आत्मविश्वास को फिर से पाने का अवसर है। अब उन्हें उम्मीद है कि वे पहले से अधिक सहजता के साथ अपने दैनिक कार्य कर सकेंगे और दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी।

हादसे ने छीना पैर, लेकिन अब नहीं छीन पाएगा मयंक के सपने-ग्राम पलारी निवासी कक्षा नवमीं के छात्र मयंक साहू के लिए सड़क दुर्घटना ने जिंदगी की राह मुश्किल कर दी थी। कुछ माह पहले हुए गंभीर हादसे में उसका एक पैर कट गया। इस घटना ने न केवल उसकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित किया, बल्कि पढ़ाई और स्कूल जाने की राह में भी बाधा खड़ी कर दी।स्कूल जाने और दोस्तों के साथ पढ़ने-लिखने की उम्र में मयंक को घर पर रहने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। पढ़ाई छूटने की चिंता भी उसे लगातार परेशान करती थी। लेकिन अब कृत्रिम पैर मिलने से उसके मन में नई उम्मीद जगी है।



डिजिटल क्रॉप सर्वे में बालोद ने रचा सफलता का नया अध्याय

98.95 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा कर प्रदेश में हासिल किया प्रथम स्थान, 7.50 लाख से अधिक खसरों का डिजिटलीकरण; 405 गांवों में शत-प्रति-शत लक्ष्य हासिल, मुख्य सचिव ने कार्ययोजना की सराहना की

बालोद ⏭ (प्रदेश रुचि)

आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सटीक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बालोद जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों और फसलों के अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के अभियान में जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में अब तक 98.95 प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता और कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को रेखांकित करती है, बल्कि कृषि क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते महत्व को भी उजागर करती है। जिले में कुल 7,58,833 खसरों में से 7,50,905 खसरों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। शेष खसरों का सर्वेक्षण पूर्ण कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। बालोद की इस उपलब्धि की राज्य के मुख्य सचिव विकासशील ने सराहना करते हुए जिले में तैयार की गई कार्ययोजना को प्रोत्साहित किया है। राज्य स्तर पर मिली इस प्रशंसा ने जिले के प्रशासनिक प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान की है।

405 गांवों में शत-प्रतिशत सर्वेक्षण अब ग्राम सभाओं में होगा सत्यापन

डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत जिले के 405 गांवों में सर्वेक्षण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अब इन गांवों में विशेष ग्राम

सभाओं के माध्यम से सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन और सत्यापन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सर्वेक्षण में दर्ज जानकारियों की पुष्टि करना और अभिलेखों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। वहीं, जिन गांवों में सर्वेक्षण का कार्य अभी शेष है, वहां विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर सतत निगरानी, मैदानी अमले के समन्वय और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से शेष लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति अपनाई जा रही है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बालोद जिले के प्रदर्शन की सराहना करते हुए शेष कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया।

विशेष श्रेणी के खसरों को भी डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने पर जोर

डिजिटल फसल सर्वेक्षण को व्यापक और समावेशी बनाने के लिए विशेष श्रेणी के खसरों को भी सर्वे के दायरे में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें वन ग्राम से राजस्व ग्राम बने गांवों, डूबान गांवों, शासकीय पट्टेदारों, संस्थागत भूमि, ग्राम नौकर तथा अधियाध्रेगहा किसानों के खसरे शामिल हैं। इन श्रेणियों के खसरों का भी शत-प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, पिछले वर्ष मैन्युअल गिरदावरी के आधार पर धान विक्रय करने वाले किसानों के खसरों का मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल सत्यापन कर डिजिटलीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य कृषि भूमि और फसलों से संबंधित जानकारियों को डिजिटल अभिलेखों में व्यवस्थित करना है, ताकि भविष्य में कृषि संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा फसल सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया जा सके।

डिजिटल कृषि व्यवस्था की ओर बढ़ता बालोद



डिजिटल क्रॉप सर्वे में बालोद की सफलता यह दर्शाती है कि सुव्यवस्थित कार्ययोजना, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और मैदानी स्तर पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से बड़े लक्ष्यों को भी समयबद्ध ढंग से हासिल किया जा सकता है। कृषि व्यवस्था में डिजिटल तकनीक का समावेश केवल आंकड़ों के संकलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेतों और फसलों से जुड़े अभिलेखों को अधिक सटीक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब बालोद प्रशासन के सामने शेष सर्वेक्षण पूरा कर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने की चुनौती है। यदि निर्धारित योजना के अनुरूप शेष कार्य भी समय पर पूर्ण होता है, तो यह उपलब्धि जिले की प्रशासनिक कार्यक्षमता के साथ-साथ डिजिटल कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगी।

14,590 खसरों का डिजिटलीकरण जारी, गांवों में कराई जा रही मुनादी

जिले में पिछले वर्ष मैन्युअल गिरदावरी के आधार पर धान बेचने वाले किसानों के 14,590 खसरों का पॉलीगॉन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इस कार्य के अंतर्गत खेतों की सीमाओं से संबंधित डिजिटल विवरण तैयार किया जा रहा है, जिससे भूमि और फसल संबंधी रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सके। संबंधित किसानों तक सर्वेक्षण की जानकारी पहुंचाने के लिए गांवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान वे अपने खेतों में उपस्थित रहकर सर्वेक्षण दल को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

किसानों की उपस्थिति और सहयोग से खेतों में बोई गई फसलों का सही सत्यापन करने में मदद मिलेगी। इससे अभिलेखों में त्रुटियों की आशंका कम होगी और भविष्य में धान विक्रय सहित कृषि संबंधी कार्यों के दौरान संभावित परेशानियों से बचने में सहायता मिलेगी।

टीमवर्क और सतत निगरानी बनी सफलता की आधारशिला : दिव्या उमेश मिश्रा

डिजिटल क्रॉप सर्वे में बालोद जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने इसे राजस्व अधिकारियों, मैदानी अमले और संबंधित कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से फसलों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करने और कृषि संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। जिले में अब तक 98.95 प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जिन 405 गांवों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, वहां विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से सर्वेक्षण सूची का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने किसानों से भी सर्वेक्षण के दौरान खेतों में उपस्थित रहकर मैदानी अमले को सहयोग देने की अपील की, ताकि फसलों का सही सत्यापन सुनिश्चित हो सके और भविष्य में धान विक्रय सहित अन्य कृषि संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न आए।



स्कूलों की चौखट तक पहुंच रहे जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर

अब स्कूलों में सिर्फ हाजिरी नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता भी होगी परीक्षा के दायरे में

बालोद ⏭ (प्रदेश रुचि)

सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक दक्षताओं को मजबूत करना और विद्यालयीन व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर जिला शिक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार दुबे पदभार संभालने के बाद से जिले के शासकीय विद्यालयों का लगातार दौरा कर रहे हैं। उनके आकस्मिक निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य स्कूलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, कमियों की पहचान करना और समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे एवं एपीसी आर.आर. कृदत्त ने दल्लीराजहरा के नयाबाजार स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी-अंग्रेजी विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां कक्षा सातवीं एवं आठवीं के विद्यार्थियों की अंग्रेजी पठन क्षमता अपेक्षित स्तर पर नहीं मिलने तथा कक्षा दूसरी एवं तीसरी के विद्यार्थियों को दो और तीन के पहाड़े याद



नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित शिक्षकों को नियमित अभ्यास, अतिरिक्त शिक्षण और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन में निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं होने तथा कैशबुक, सेवा पुस्तिका और अन्य अभिलेखों के संधारण में कमियां भी सामने आईं। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधितों को तीन दिवस के भीतर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। अभिलेखीय लापरवाही के मामले में संबंधित लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह माध्यमिक शाला सुरेगांव में मध्याह्न भोजन के निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं होने, पोषण वाटिका का अभाव तथा मानक के अनुरूप दाल उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सुधार के निर्देश दिए गए। हायर सेकेंडरी स्कूल पीनकापार के निरीक्षण में प्रभारी प्राचार्य कमलेश कुमार सहित तीन शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पाठ योजना तैयार नहीं किए जाने की स्थिति पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हायर सेकेंडरी स्कूल सुरेगांव एवं भंडेरा में शिक्षण कार्य की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान एबीओ अश्वन कुमार साहू भी उपस्थित रहे।



निरीक्षण नहीं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास

जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे की इस पहल का व्यापक उद्देश्य विद्यालयों में केवल औपचारिक उपस्थिति सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के वास्तविक सीखने के स्तर में सुधार लाना है। प्राथमिक कक्षाओं में पहाड़े, भाषा और पठन क्षमता जैसी बुनियादी दक्षताएं आगे की शिक्षा की नींव होती हैं। यदि इसी स्तर पर कमियां रह जाती हैं, तो उनका असर विद्यार्थियों की पूरी शैक्षणिक यात्रा पर पड़ सकता है। यही कारण है कि निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों के साथ मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, पाठ योजना और वित्तीय एवं सेवा संबंधी अभिलेखों की भी समीक्षा की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था में स्थायी बदलाव के लिए निरीक्षण के साथ निरंतर निगरानी, जवाबदेही और सुधार के परिणामों का आकलन भी जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारी की सक्रियता से यह उम्मीद मजबूत होती है कि समयबद्ध सुधार और नियमित मूल्यांकन के माध्यम से बालोद जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी। अब इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव दिखाई देता है, यह आगामी निरीक्षणों और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में होने वाले सुधार से स्पष्ट होगा।



सीएम हेल्पलाइन पर 2.31 लाख शिकायतें, 88.85% निराकरण का दावा; सवाल यह कि जनता को कितनी राहत?

सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां, 25,854 शिकायतें अब भी लंबित; शिकायत बंद होना और समस्या का स्थायी समाधान होना क्या एक ही बात है?

रायपुर

सुशासन की असली पहचान सरकारी आंकड़ों की चमक से नहीं, बल्कि आम नागरिक की जिंदगी में आने वाले बदलाव से होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने उत्साहजनक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ कुछ ऐसे सवाल भी सामने आते हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। आखिर शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत कितना भी बेहतर क्यों न हो, क्या इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि हर शिकायतकर्ता को वास्तविक और स्थायी राहत मिल गई है?

सरकार के अनुसार, 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन पर 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया गया, जबकि 25 हजार 854 शिकायतें अब भी लंबित हैं। इस तरह निराकरण का आंकड़ा 88.85 प्रतिशत बताया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित हेल्पलाइन कार्यालय में व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान और नागरिकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

88.85 प्रतिशत निराकरण, लेकिन समाधान की गुणवत्ता का पैमाना क्या?

हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1,500 से 2,000 शिकायतें आने का आंकड़ा बताता है कि नागरिकों की समस्याएं बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। सरकार के लिए यह व्यवस्था प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच आसान बनाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत अपने आप में सफलता का अंतिम प्रमाण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि निराकृत शिकायतों में कितने मामलों में समस्या का स्थायी समाधान हुआ? कितने शिकायतकर्ताओं ने समाधान की पुष्टि की? कितने मामलों में शिकायत बंद होने के बाद नागरिकों को दोबारा उसी समस्या का सामना करना पड़ा? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने पर ही हेल्पलाइन की वास्तविक प्रभावशीलता का आकलन संभव होगा।

ट्रांसफॉर्मर बदला, आवास की किस्त मिली, पेंशन शुरू; क्या यही है पूरी तस्वीर?

सरकार ने हेल्पलाइन के जरिए राहत मिलने के कुछ उदाहरण भी सामने रखे हैं। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर बदलने से 80 से 85 परिवारों को बिजली मिली। जशपुर जिले के एक हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित दूसरी किस्त के रूप में 55 हजार रुपये मिले, जबकि मुंगेली जिले में नौ महीने से रुकी एक हितग्राही



की पेंशन दोबारा शुरू हुई। ये उदाहरण निश्चित रूप से राहत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मगर सवाल यह भी है कि जिन नागरिकों को बिजली, पेंशन या आवास की राशि के लिए हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा, उनकी समस्या पहले ही नियमित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत क्यों नहीं सुलझ सकी? क्या विभागीय निगरानी इतनी कमजोर है कि सामान्य नागरिक सेवाओं के लिए भी शिकायत दर्ज कराना जरूरी हो रहा है?

यदि किसी पात्र हितग्राही को नौ महीने तक पेंशन नहीं मिलती, तो शिकायत के बाद उसका शुरू होना राहत तो है, लेकिन यह देरी स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की मांग भी करती है।

लंबित शिकायतें प्रशासन के सामने चुनौती

25,854 शिकायतों का लंबित रहना बताता है कि व्यवस्था के सामने अभी काम बाकी है। इन शिकायतों में किन विभागों का प्रदर्शन कमजोर है, कौन से जिले पीछे हैं और कितने मामले निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से लंबित हैं—इनका विस्तृत विवरण सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी शिकायतों के आंकड़ों का विश्लेषण कर मूल कारणों की पहचान करने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि इन निर्देशों का असर विभागों की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है या नहीं।



सुशासन की कसौटी पर हेल्पलाइन

सीएम हेल्पलाइन 1076 को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटरों में प्रचार-प्रसार करने की योजना है। दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों तक इसकी पहुंच बढ़ाना भी जरूरी है। लेकिन प्रचार से अधिक महत्वपूर्ण है भरोसा। नागरिक तभी हेल्पलाइन को प्रभावी मानेंगे, जब उनकी शिकायत समय पर सुनी जाए, समाधान की गुणवत्ता की जांच हो और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई दिखाई दे।आखिर-कार, हेल्पलाइन की सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि कितनी शिकायतें बंद हुईं, बल्कि इससे कि कितनी समस्याएं वास्तव में खत्म हुईं। सरकारी आंकड़े शुरुआती उपलब्धि का संकेत जरूर देते हैं, लेकिन पारदर्शी फीडबैक, लंबित मामलों का विवरण और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था ही यह साबित कर सकेगी कि 1076 सुशासन का प्रभावी माध्यम बन रही है या अभी उसे लंबा सफर तय करना है।



मतदाता सूची से संसद तक सियासी संग्राम, कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने-सामने

नई दिल्ली। देश की राजनीति में कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच टकराव एक बार फिर गहराता दिखाई दे रहा है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी INDIA गठबंधन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष इन मुद्दों को लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता से जोड़ रहा है, जबकि इस पूरे विवाद में निर्वाचन प्रक्रिया की वैधानिकता और संस्थागत जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है।

SIR और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर विपक्ष के सवाल, राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन का विरोध तेज

अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में INDIA गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर विरोध मार्च निकाला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी नेताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनुचित ढंग से नहीं हटना चाहिए। विपक्ष ने मतदाता सूची में बदलाव की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने, नाम हटाने से पहले उचित सूचना देने और प्रभावित मतदाताओं को प्रभावी अपील का अवसर उपलब्ध कराने जैसी मांगें उठाई हैं।

इस बीच, विवाद न्यायिक स्तर पर भी पहुंच गया है। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जवाब मांगा। याचिका में SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से संबंधित आपत्तियां उठाई गई हैं। न्यायालय द्वारा जवाब मांगा जाना इन आरोपों की पुष्टि नहीं है; मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष और न्यायिक परीक्षण महत्वपूर्ण होंगे।

राजनीतिक दृष्टि से यह विवाद कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच व्यापक संघर्ष का हिस्सा बनता जा रहा है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही का प्रश्न बता रही है, जबकि इस मुद्दे पर आरोपों और उनके जवाबों का परीक्षण तथ्यों, निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना आवश्यक है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि, राजनीतिक आरोपों के बीच यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि बहस तथ्यों पर आधारित रहे और मतदाताओं का निर्वाचन प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। अब निगाहें इस बात पर हैं कि निर्वाचन आयोग और संबंधित पक्ष न्यायिक कार्यवाही के दौरान क्या स्पष्टीकरण देते हैं तथा राजनीतिक दल इस विवाद को संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किस दिशा में ले जाते हैं।



लोकतंत्र, संविधान एवं चुनाव सुधार

विशेष आलेख । प्रदेशरुचि

भारत का लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं, संघर्षों और सामूहिक चेतना का जीवंत प्रतिबिंब है। इसकी आत्मा संविधान में बसती है, इसकी शक्ति जनता के मताधिकार में निहित है और इसकी प्रतिष्ठा उन संस्थाओं की निष्पक्षता से निर्धारित होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जिस संवैधानिक यात्रा का आरंभ किया, वह विविधताओं से भरे राष्ट्र को समान अधिकारों, न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता के सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक प्रयास था।आज जब भारतीय लोकतंत्र निरंतर बदलते सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवेश से गुजर रहा है, तब संविधान की मूल भावना को अक्षुण्ण रखते हुए चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने पर गंभीर विमर्श आवश्यक हो गया है।

जनविश्वास की बुनियाद पर ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव

संविधान : लोकतांत्रिक भारत का नैतिक आधार

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक ऐसे गणराज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया, जहां व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल आदर्श वाक्य न रहकर शासन और समाज के मार्गदर्शक सिद्धांत बनें। डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की परिकल्पना की, जिसमें सत्ता किसी व्यक्ति या संस्था की निरंकुश इच्छा पर निर्भर न रहे, बल्कि कानून, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से अनुशासित हो।

संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ शासन की शक्तियों की सीमाएं भी निर्धारित करता है। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या तथा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानून के शासन को सुदृढ़ करती है। इन संस्थाओं के बीच संतुलन लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। इसलिए संविधान की रक्षा केवल सरकारी संस्थाओं का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल और सार्वजनिक पदाधिकारी की साझा जिम्मेदारी है।

चुनाव : जनादेश का उत्सव, जनविश्वास की कसौटी

भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक समानता का महत्वपूर्ण आधार है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति और

सामाजिक पृष्ठभूमि से परे प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। मतदान केंद्र पर एक सामान्य नागरिक का मत भी संवैधानिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना किसी प्रभावशाली व्यक्ति का। लेकिन चुनाव की सार्थकता केवल मतदान प्रतिशत या निर्वाचन परिणाम तक सीमित नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता का अनुभव होना भी उतना ही आवश्यक है। मतदाता सूची की शुद्धता, प्रत्याशियों की जानकारी, राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता, चुनाव प्रचार में मर्यादा तथा निर्वाचन संबंधी शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण इस विश्वास को मजबूत बनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनावों के लिए आवश्यक है।

चुनाव सुधार : समय की आवश्यकता

लोकतंत्र की जीवंतता इस बात में निहित है कि वह अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की क्षमता रखता है। बदलते समय के साथ चुनावी व्यवस्था में सुधार भी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए।

पहला सुधार—राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता। चुनावों में धनबल की भूमिका लोकतांत्रिक समानता के लिए चुनौती बन सकती है। राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे, चुनावी व्यय और वित्तीय जवाबदेही से संबंधित जानकारी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध होनी चाहिए, जो कानून के अनुरूप हो और नागरिकों को राजनीतिक वित्तपोषण समझने में सहायता करे।

दूसरा सुधार—आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रत्याशियों की जानकारी। मतदाताओं को प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक मामलों से संबंधित कानूनी रूप से अपेक्षित जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, आरोप और दोषसिद्धि के बीच अंतर का सम्मान करते हुए न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना भी आवश्यक है।

तीसरा सुधार—मतदाता सूची की शुद्धता। मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है। हालांकि, इस प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम अनुचित रूप से हटने से रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नाम जोड़ने, सुधार कराने और हटाए जाने के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया सरल, समयबद्ध तथा सुलभ बनाई जानी चाहिए।

चौथा सुधार—चुनाव प्रचार में जवाबदेही। राजनीतिक विमर्श का स्तर लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक होता है। व्यक्तिगत आरोपों, अप्रमाणित सूचनाओं और समाज में विभाजन पैदा करने वाले प्रचार के स्थान पर नीतियों, उपलब्धियों, कमियों और भविष्य की योजनाओं पर आधारित बहस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पांचवां सुधार—तकनीक और पारदर्शिता का संतुलन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, मतदाता सत्यापन और मतगणना से संबंधित प्रक्रियाओं पर नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम, प्रभावी शिकायत निवारण और पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी आवश्यक है। तकनीकी व्यवस्था के प्रति विश्वास केवल दावों से नहीं, बल्कि जांच योग्य प्रक्रियाओं और पारदर्शी संस्थागत उत्तरदायित्व से निर्मित होता है।

सत्ता और विपक्ष : लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ

संसदीय लोकतंत्र में सरकार का दायित्व नीतियों को लागू करना और जनादेश के अनुरूप शासन चलाना है, जबकि विपक्ष की भूमिका सरकार के कार्यों की समीक्षा करना, जनहित के प्रश्न उठाना और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना है। सरकार की आलोचना को स्वतः राष्ट्रविरोधी मानना लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित कर सकता है। इसी प्रकार, प्रत्येक सरकारी निर्णय का बिना तथ्यात्मक परीक्षण विरोध करना भी रचनात्मक राजनीति की भावना के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण असहमति को तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मर्यादा के साथ व्यक्त करना है। संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रश्नों पर संवाद, बहस और जवाबदेही का सर्वोच्च राजनीतिक मंच भी है। जब जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा होती है, संसदीय समितियां प्रभावी ढंग से काम करती हैं और जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होता है।

नागरिक चेतना : लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति

लोकतंत्र की मजबूती केवल संवैधानिक संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती। जागरूक नागरिक उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। मतदाता यदि प्रत्याशियों के कार्यों, नीतियों और सार्वजनिक आचरण का मूल्यांकन करें, अपुष्ट सूचनाओं से सावधान रहें तथा मतदान को अधिकार के साथ-साथ नागरिक दायित्व भी समझें, तो लोकतांत्रिक संस्कृति अधिक परिपक्व बन सकती है। युवाओं, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों की राजनीतिक सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तभी व्यापक अर्थों में प्रतिनिधिक बनता है, जब निर्णय प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज सुनी जाए और सार्वजनिक नीतियों में उनकी आवश्यकताओं को स्थान मिले। डिजिटल युग में नागरिकों की यह जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित राजनीतिक सूचनाओं की सत्यता जांचना, अफवाहों से बचना और मतभेदों के बावजूद संवाद की मर्यादा बनाए रखना स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है।

संविधान की आत्मा, जनता का विश्वास

भारत का लोकतंत्र एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का स्थायी समाधान संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत निष्पक्षता और नागरिक सहभागिता को मजबूत करने में निहित है। चुनाव सुधारों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाना या किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होना चाहिए, जिसमें मतदाता स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सके, प्रत्याशियों को समान अवसर मिले, राजनीतिक दल जवाबदेह रहें और निर्वाचन प्रक्रिया पर नागरिकों का विश्वास बना रहे। संविधान हमें अधिकार देता है, संस्थाओं को दायित्व सौंपता है और लोकतंत्र हमें असहमति के बीच सहअस्तित्व का मार्ग दिखाता है। इन तीनों के बीच संतुलन ही एक सशक्त गणराज्य की पहचान है। क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक विजय किसी राजनीतिक दल की जीत में नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकार, संविधान की गरिमा और जनविश्वास की अक्षुण्णता में निहित है।

रुपये की कमजोरी से अर्थव्यवस्था पर दबाव, RBI के सामने स्थिरता की चुनौती

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने इन दिनों मुद्रा बाजार की स्थिरता बनाए रखने और महंगाई पर नियंत्रण रखने की दोहरी चुनौती खड़ी है। रुपये की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं ने आर्थिक नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। 16 अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष भारतीय रुपये में लगभग छह प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मुद्रा बाजार में जारी इस दबाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नीतिगत कदमों पर आर्थिक जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।

रुपये की गिरावट के पीछे क्या हैं कारण?

किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य केवल घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति से निर्धारित नहीं होता, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता जैसी परिस्थितियां रुपये पर दबाव बढ़ा सकती हैं। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पूंजी निकालते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत कमजोर होने की आशंका रहती है। इसका प्रभाव आयात पर निर्भर क्षेत्रों पर विशेष रूप से पड़ सकता है। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी और अन्य आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ने से घरेलू बाजार में महंगाई का दबाव पैदा हो सकता है।

आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर?

रुपये की कमजोरी का प्रभाव धीरे-धीरे आम उपभोक्ता तक पहुंच सकता है। आयातित कच्चे माल और ऊर्जा की लागत बढ़ने पर परिवहन, विनिर्माण तथा अन्य क्षेत्रों के खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर पड़ने की आशंका रहती है। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आवास, वाहन और कारोबारी ऋण महंगे हो सकते हैं। इससे मासिक किस्तों का बोझ बढ़ने और निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होने की संभावना रहती है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव बैंकों की ब्याज दरों, ऋण की शर्तों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

आर्थिक स्थिरता की कसौटी पर भारत



भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा परिस्थिति केवल मुद्रा बाजार की चुनौती नहीं, बल्कि विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की परीक्षा भी है। रुपये में उतार-चढ़ाव अपने आप में आर्थिक संकट का संकेत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जारी कमजोरी महंगाई और कारोबारी लागत पर दबाव बढ़ा सकती है। ऐसे समय में सरकार और केंद्रीय बैंक के लिए आवश्यक है कि वे आर्थिक स्थिरता, निवेशकों के विश्वास और विकास की गति के बीच संतुलन बनाए रखें। आने वाले महीनों में वैश्विक बाजारों की दिशा, विदेशी निवेश का रुख और महंगाई के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की आगे की राह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

RBI के सामने संतुलन साधने की चुनौती

मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखना केंद्रीय बैंक की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। रुपये पर दबाव बढ़ने की स्थिति में RBI मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, बैंकिंग प्रणाली की नकदी का प्रबंधन तथा अन्य मौद्रिक उपायों का सहारा ले सकता है। ब्याज दरों में संभावित बदलाव भी इसी व्यापक आर्थिक विमर्श का हिस्सा है। हालांकि, ब्याज दरों में वृद्धि का निर्णय केवल रुपये की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। महंगाई की दर, आर्थिक विकास, ऋण की मांग और वैश्विक परिस्थितियों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।



नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी बताई गई नई दरों के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। सरकार के इस कदम को पेट्रोलियम निर्यात से प्राप्त राजस्व और ऊर्जा क्षेत्र की आर्थिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की नीति के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है विंडफॉल टैक्स और क्यों लगाया जाता है?

विंडफॉल टैक्स एक विशेष प्रकार का कर है, जिसे सरकार उन परिस्थितियों में लागू कर सकती है, जब किसी उद्योग या कंपनी को बाजार की असाधारण परिस्थितियों के कारण सामान्य से अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। पेट्रोलियम क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और तैयार ईंधन के निर्यात से मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए ऐसे करों का निर्धारण किया जाता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का आयात, शोधन और निर्यात आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्यात शुल्क की दरों में बदलाव का सीधा प्रभाव तेल शोधन कंपनियों की लागत और मुनाफे पर पड़ सकता है।

पेट्रोल पर सख्ती, डीजल को अपेक्षाकृत राहत

नए शुल्क ढांचे में पेट्रोल निर्यात पर कर बढ़ाया गया है, जबकि डीजल पर इसे कम किया गया है। इससे दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात संबंधी आर्थिक समीकरणों में बदलाव संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार, निर्यात शुल्क में वृद्धि से संबंधित उत्पाद के निर्यात पर मिलने वाला शुद्ध लाभ प्रभावित हो सकता है। वहीं, शुल्क में कटौती निर्यातकों को कुछ राहत प्रदान कर सकती है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव अंतरराष्ट्रीय कीमतों, उत्पादन लागत और वैश्विक मांग पर निर्भर करेगा।

क्या आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर?

निर्यात शुल्क में बदलाव का अर्थ घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में तत्काल परिवर्तन होना नहीं है। देश में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, विनिमय दर, करों और तेल विपणन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं। इसलिए निर्यात पर कर बढ़ने या घटने से आम उपभोक्ताओं को सीधे राहत मिलने अथवा अतिरिक्त बोझ पड़ने का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

ऊर्जा सुरक्षा और राजस्व के बीच संतुलन की चुनौती

भारत की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन, कृषि, उद्योग और व्यापार की गतिविधियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है—एक ओर ऊर्जा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना और दूसरी ओर राजस्व हितों की रक्षा करना। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के इस दौर में पेट्रोलियम निर्यात शुल्क का संतुलित निर्धारण आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बहरहाल, पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में यह बदलाव केवल कर व्यवस्था का संशोधन नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक ऊर्जा परिस्थितियों के बीच भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजस्व प्रबंधन से जुड़ा महत्वपूर्ण नीतिगत कदम माना जा सकता है।

जेम्स बॉन्ड की फिल्म से हकीकत तक! एलन मस्क की रोडस्टर में दिखा 'टर्बो बूस्ट' का रोमांच

रॉकेट तकनीक से हवा में उछलने वाली इलेक्ट्रिक सुपरकार ने बटोरी सुर्खियां, 2028 से उत्पादन शुरू करने की तैयारी; एलन मस्क की पोस्ट ने 1983 की जेम्स बॉन्ड फिल्म की यादें कीं ताजा

टेक्नोलॉजी डेस्क। प्रादेश रुचि

नई दिल्ली। हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देने वाली तकनीक जब वास्तविक दुनिया में आकार लेने लगे, तो कल्पना और विज्ञान के बीच की दूरी कम होती नजर आने लगती है। कुछ ऐसा ही नजारा एलन मस्क की बहुप्रतीक्षित टेस्ला रोडस्टर को लेकर सामने आया है। रॉकेट तकनीक, असाधारण रफ्तार और हवा में कलाबाजी दिखाने की क्षमता से जुड़ी इस कार ने न केवल ऑटोमोबाइल जगत का ध्यान खींचा है, बल्कि 1983 की जेम्स बॉन्ड फिल्म 'नेवर से नेवर अगेन' में दिखाई



गई रॉकेट जैसी तकनीक की यादें भी ताजा कर दी हैं। एलन मस्क ने अपनी कार के प्रदर्शन की तुलना फिल्मी दुनिया की कल्पनाओं से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "Elon Musk just made Turbo Boost a reality." इसके साथ उन्होंने कहा, "A bunch of guys my age have been waiting our whole lives for this." यानी एलन मस्क ने 'टर्बो बूस्ट' को हकीकत बना दिया है और उनकी उम्र के कई लोग जीवनभर ऐसी तकनीक का इंतजार करते रहे हैं।

जेम्स बॉन्ड की फिल्म और भविष्य की कार

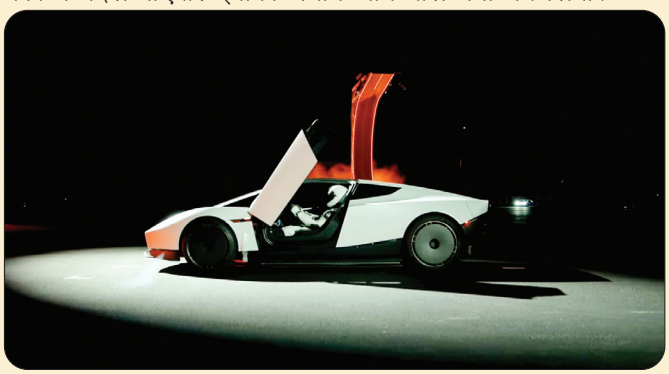
वर्ष 1983 में रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड की फिल्म 'नेवर से नेवर अगेन' में एजेंट 007 की तेज रफ्तार और तकनीकी खूबियों से लैस कार ने दर्शकों को रोमांचित किया था। उस दौर में ऐसी तकनीकें बड़े पर्दे पर कल्पना और मनोरंजन का हिस्सा थीं। आज इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत इंजीनियरिंग के विकास ने इसी तरह की कल्पनाओं को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। हालांकि, फिल्म में दिखाई गई तकनीक और टेस्ला की वास्तविक इंजीनियरिंग में अंतर है। दोनों की तुलना का आकर्षण उस रोमांच में है, जिसमें कार सामान्य वाहन की सीमाओं से आगे जाती दिखाई देती है।

रॉकेट तकनीक से लैस रोडस्टर

टेस्ला की नई पीढ़ी की रोडस्टर में स्पेसएक्स की तकनीक पर आधारित थ्रस्टर प्रणाली को लेकर खास उत्सुकता है। प्रदर्शन के दौरान कार को विशेष रैंप पर उछलते, हवा में घूमते और असाधारण गतिविधियां करते दिखाया गया। कंपनी ने इसकी गति को लेकर भी बड़े दावे किए हैं। टेस्ला के अनुसार, कार लगभग 96.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक सेकंड से भी कम समय में हासिल करने की क्षमता रख सकती है। हालांकि, इन दावों और प्रदर्शन में दिखाई गई क्षमताओं की पुष्टि उत्पादन मॉडल के स्वतंत्र परीक्षण तथा सुरक्षा मानकों के आधार पर ही हो सकेगी।

2028 पर टिकी दुनिया की निगाहें

टेस्ला ने नई रोडस्टर का उत्पादन 2028 में शुरू करने की योजना बताई है। लेकिन उत्पादन की शुरुआत, ग्राहकों को डिलीवरी और अलग-अलग देशों में उपलब्धता की समयसीमा अलग हो सकती है। कार की अंतिम कीमत और भारत में संभावित लॉन्च को लेकर भी स्पष्ट जानकारी का इंतजार है। नई रोडस्टर ने एक बार फिर साबित किया है कि भविष्य की तकनीक की कल्पना केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहती। जेम्स बॉन्ड के दौर में जो रोमांच सिनेमाई पर्दे पर दिखाई देता था, आज वही भावना अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में नई संभावनाएं पैदा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टेस्ला इस तकनीकी रोमांच को सुरक्षित, भरोसेमंद और व्यावहारिक उत्पादन कार में बदल पाएगी? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा।



बापू बाजार : मदद ऐसी कि स्वाभिमान भी रहे बरकरार

आजमगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना की पहल बनी सामाजिक बदलाव की मिसाल, जरूरत-मंदों को सम्मान के साथ राहत और विद्यार्थियों को समाज सेवा की सीख



प्रो. डॉ. हसीन खान समन्वयक, बापू बाजार

किसी जरूरतमंद की मदद करना मानवीय संवेदना है, लेकिन मदद इस तरह की जाए कि उसकी आर्थिक विवशता उसके आत्मसम्मान पर बोझ न बने, तो सेवा का अर्थ और व्यापक हो जाता है। उत्तर प्रदेश के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में आयोजित बापू बाजार इसी विचार को व्यवहार में उतारने की एक सार्थक पहल है। यहां जरूरतमंद परिवारों को कपड़े और घरेलू उपयोग की वस्तुएं मुफ्त बांटने के बजाय पांच, दस, पंद्रह और बीस रुपये जैसी मामूली कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। लोग अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार सामान चुनते हैं, निर्धारित राशि चुकाते हैं और सम्मान के साथ घर लौटते हैं। हम आज विज्ञान के सहारे चांद और मंगल पर तो जरूर पहुंच गए हैं, किंतु दीवार के उस पार बैठे पड़ोसी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बीमार है, भूखा है, वस्त्रहीन और अभावग्रस्त हैं। यह बापू बाजार उसी दीवार को गिराने तथा उस पड़ोसी तक पहुंचने की एक शानदार पहल है, जिसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बापू बाजार वास्तव में समाज के अंतिम व्यक्ति जिसे कभी महात्मा गांधी ने दरिद्र नारायण कहा था, उन तक पहुंचने की एक सम्मान सहित कोशिश है। बापू बाजार का उद्देश्य केवल कम कीमत पर उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराना नहीं है। यह समाज के वंचित वर्गों को राहत देने के साथ उनके स्वाभिमान की रक्षा करने, संसाधनों का सदुपयोग करने और युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रयास भी है। आमतौर पर दान की व्यवस्था में वस्तु देने वाला और उसे प्राप्त करने वाला दो अलग-अलग भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कई बार अनजाने में यह स्थिति सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मन में संकोच भी पैदा कर सकती है। बापू बाजार इस पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सहायता को सम्मानजनक सहभागिता का रूप देता है। यहां जरूरतमंद व्यक्ति अपनी पसंद से सामान चुनता है और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप मामूली राशि देकर उसे प्राप्त करता है। इस बाजार में उपलब्ध वस्तुएं समाज के उन परिवारों के लिए उपयोगी साबित होती हैं, जिनके लिए कपड़े, बर्तन, किताबें और अन्य घरेलू जरूरतों की पूर्ति भी आर्थिक परिस्थितियों के कारण कठिन होती है। वहीं, जिन परिवारों के पास उपयोग में न आने वाली अतिरिक्त वस्तुएं हैं, वे उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सहभागी बनते हैं। इस प्रकार एक ओर अनुपयोगी वस्तुओं का सार्थक इस्तेमाल होता है, तो दूसरी ओर जरूरतमंद परिवारों को कम खर्च में उपयोगी सामान मिल जाता है। बाजार से प्राप्त राशि बापू स्वाभिमान कोष में जमा की जाती है। इस व्यवस्था में सेवा, संसाधनों का पुनः उपयोग और स्वाभिमान-तीनों का समन्वय दिखाई देता है। बापू बाजार की अवधारणा को पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रो. सुंदरलाल के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया गया। उस समय मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम समन्वयक था। इसी दौरान इस विचार को व्यवहार में लाने और विश्वविद्या-लय के विद्यार्थियों तथा स्थानीय समाज को इससे जोड़ने का अवसर मिला। प्रारंभ से ही बापू बाजार के आयोजन से जुड़कर मैंने अनुभव किया कि सामाजिक सरोकारों को शिक्षा का हिस्सा बनाने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

समय के साथ यह आयोजन धीमा पड़ गया और इसकी नियमितता प्रभावित हुई। लेकिन किसी अच्छी पहल का महत्व समय बीतने के साथ कम नहीं होता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के कुलपति प्रो. संजीव कुमार की पहल ने बापू



बाजार को पुनः सक्रिय करने का अवसर दिया। उनके निर्देशानुसार मुझे विश्वविद्यालय में बापू बाजार के समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुलसचिव श्री अमृतलाल एवं विश्वविद्यालय परिवार, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और संबंधित लोगों के सहयोग से इस पहल को फिर व्यवस्थित रूप दिया गया।

9 अक्टूबर 2026 को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में द्वितीय बापू बाजार का आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से किया गया। इस आयोजन ने न केवल जरूरतमंद परिवारों को उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने का अवसर दिया, बल्कि विश्वविद्यालय की सामाजिक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। इससे पहले आयोजित बापू बाजार में आजमगढ़ और मऊ जनपद के लगभग 48 महाविद्यालयों ने अपने संसाधनों के साथ भागीदारी की थी।

बापू बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य 'मैं नहीं, आप' (Not Me, But You) स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने की प्रेरणा देता है। बापू बाजार इसी भावना को व्यावहारिक अनुभव में बदलने का माध्यम है।पुस्तकीय शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान देती है, लेकिन समाज के बीच काम करने का अनुभव उन्हें संवेदनशील नागरिक बनाता है। बापू बाजार में सहभागिता के दौरान विद्यार्थियों में सहयोग, समानता, श्रम के प्रति सम्मान, सामूहिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना जैसे मूल्य विकसित होते हैं। वे समझते हैं कि समाज की समस्याएं केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं हैं। उनके समाधान में नागरिकों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से बापू बाजार विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सामाजिक जीवन की प्रयोगशाला है। यहां वे सेवा को केवल दया या दान के रूप में नहीं, बल्कि समानता, सहभागिता और मानवीय गरिमा के सम्मान के रूप में देखना सीखते हैं। आजमगढ़ में आयोजित द्वितीय बापू बाजार में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के कुलपति प्रो. एन.के. शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अभिनव प्रयोग को देखकर उन्होंने बलिया विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में भी बापू बाजार आयोजित करने की बात कही। यह इस पहल के विस्तार की दिशा में उत्साहजनक संकेत है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ रही हैं। यदि ये संस्थान अपने स्थानीय परिवेश और जरूरतों के अनुरूप बापू बाजार की अवधारणा अपनाएं, तो अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदाय के बीच विश्वास, सहयोग और सहभागिता का संबंध भी मजबूत होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पूर्व विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को जोड़कर इस पहल को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए बड़े बजट या जटिल व्यवस्था की अनिवार्यता नहीं है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों में समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता और उसकी गरिमा का विशेष महत्व था। बापू बाजार इसी भावना को व्यवहार में उतारने का एक प्रयास है। सामाजिक बदलाव के लिए हमेशा बड़े अनुदान या व्यापक संसाधनों की जरूरत नहीं होती। संवेदनशील सोच, सामूहिक सहभागिता और सम्मानजनक व्यवस्था भी परिवर्तन की मजबूत आधारशिला बन सकती है।

महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में बापू बाजार का पुनः आयोजन इसी विश्वास को मजबूत करता है। कुलपति प्रो. संजीव कुमार की पहल, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की सक्रियता और विश्वविद्यालय परिवार के सहयोग से इस विचार को नई दिशा मिली है।



नाना पाटेकर : संघर्ष, अभिनय, सादगी और मानवीय संवेदना से गढ़ा एक असाधारण व्यक्तित्व



Bishwa Nath Jha

कुछ कलाकार पर्दे पर किरदार निभाते हैं, कुछ उनमें अपना रंग भरते हैं, लेकिन विरले कलाकार ऐसे होते हैं जो किरदार को ही अपना जीवन बना देते हैं। नाना पाटेकर इसी विरल परंपरा के अभिनेता थे। उनकी आवाज में जीवन की तपिश, संवादों में विद्रोह की धार, आंखों में अनुभव की गहराई और मौन में ऐसी संवेदना थी, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती थी। वे अभिनय नहीं करते थे, किरदार को जीते थे। विश्वनाथ पाटेकर से नाना पाटेकर तक की उनकी यात्रा संघर्ष, साधना और आत्मविश्वास से निर्मित हुई। मराठी रंगमंच की तपती जमीन से शुरू हुआ उनका सफर लगभग पांच दशकों तक हिंदी और मराठी सिनेमा के विस्तृत आकाश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता रहा। उनकी कला में समय के साथ परिपक्वता आती गई और हर भूमिका के साथ उन्होंने अभिनय की नई संभावनाओं को सामने रखा। 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में उनके निधन के साथ भारतीय सिनेमा ने अपने एक ऐसे सशक्त कलाकार को खो दिया, जिसकी पहचान किसी एक छवि, शैली या भूमिका तक सीमित नहीं रही। यही कारण है कि उनकी रचनात्मक विरासत समय की धूल से धुंधली होने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।

सिनेमा से समाज तक संवेदना की यात्रा

उन्होंने अभिनय को चकाचौंध से निकालकर जीवन की कठोर सच्चाइयों के करीब खड़ा किया। नायक, खलनायक, चरित्र अभिनेता, हास्य कलाकार और निर्देशक, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, खामोशी, वेलकम और नटसम्राट उनके बहुरंगी अभिनय संसार के जीवंत प्रमाण हैं। उत्कृष्ट अभिनय के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वर्ष 2013 का पद्म श्री उनके रचनात्मक अवदान की प्रतिष्ठित स्वीकृतियां हैं।लेकिन नाना पाटेकर का व्यक्तित्व कैमरे की रोशनी से कहीं आगे तक फैला था। किसानों और ग्रामीण समाज की पीड़ा से उनका जुड़ाव, नाम फाउंडेशन के माध्यम से जल संरक्षण और ग्रामीण पुनर्वास के प्रयास तथा भारतीय सेना के प्रति उनका गहरा सम्मान उनके भीतर बसे संवेदनशील मनुष्य की पहचान थे। सादगी उनके स्वभाव में थी और सामाजिक सरोकार उनके जीवन में। नाना पाटेकर की असली विरासत उनकी फिल्मों से आगे है। उन्होंने अपने अभिनय से किरदारों को आवाज दी और अपने जीवन से इंसानियत को अर्थ। यही कारण है कि पर्दा भले ही शांत हो जाए, लेकिन उनकी आवाज, उनके संवाद और उनकी संवेदना भारतीय सिनेमा की स्मृतियों में सदियों तक गूंजती रहेगी।

संघर्ष की जमीन से अभिनय के आकाश तक

नाना पाटेकर का जीवन किसी तैयार फिल्मी पटकथा की तरह आसान नहीं था। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ। कला के प्रति रुचि ने उन्हें मुंबई के सर जेजे. स्कूल ऑफ आर्ट्स तक पहुंचाया और इसके बाद रंगमंच उनके रचनात्मक जीवन का महत्वपूर्ण आधार बना। रंगमंच अभिनय की ऐसी पाठशाला है, जहां कलाकार को कैमरे की सुविधा नहीं मिलती। वहां संवाद, देहभाषा, आवाज, मौन और भाव सब कुछ कलाकार को स्वयं साधना पड़ता है। नाना पाटेकर के अभिनय में आगे चलकर जो तीव्रता दिखाई दी, उसकी जड़ें इसी रंगमंचीय प्रशिक्षण में थीं। उन्होंने अभिनय को केवल संवाद बोलने की कला नहीं माना, बल्कि चरित्र के भीतर उतरकर उसकी मानसिक दुनिया को समझने का माध्यम बनाया।फिल्मों में प्रवेश के बाद शुरुआती दौर में उन्हें तत्काल वह लोकप्रियता नहीं मिली, जो पारंपरिक नायकों को मिलती थी। लेकिन उन्होंने अपनी राह अलग चुनी। उनका चेहरा पारंपरिक अर्थों में रोमांटिक नायक की छवि से मेल नहीं खाता था और उनकी आवाज में भी वह बनावटी मिठास नहीं थी, जो व्यावसायिक सिनेमा के कई किरदारों में सुनाई देती थी। उनके पास था यथार्थ का स्पर्श, अनुभव की कठोरता और भावनाओं को भीतर से पकड़ लेने की क्षमता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

'गमन' से राष्ट्रीय पहचान तक

नाना पाटेकर ने 1978 की फिल्म गमन से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में लगातार काम किया। 1988 में मीरा नायर की सलाम बॉम्बे! ने उनके अभिनय को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद परिंदा ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। परिंदा में उनका अभिनय केवल एक नकारात्मक चरित्र का चित्रण नहीं था। उन्होंने हिंसा और अपराध की दुनिया में फंसे व्यक्ति के भीतर मौजूद मानसिक द्वंद्व को भी प्रभावशाली ढंग से सामने रखा। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनकी संवाद-अदायगी, आंखों की भाषा और चेहरे की कठोरता ने दर्शकों को यह अनुभव कराया कि अभिनय केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि चरित्र की आंतरिक बेचैनी को जीना भी है। इसके बाद क्रांतिवीर ने नाना पाटेकर को एक अलग ऊंचाई दी। फिल्म में उन्होंने सामाजिक अन्याय, व्यवस्था से

असंतोष और आम आदमी के आक्रोश को आवाज दी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनके संवाद केवल संवाद नहीं रह गए। वे जनभावना की अभिव्यक्ति बन गए। यही वह दौर था, जब नाना पाटेकर की आवाज भारतीय सिनेमा की सबसे पहचानने योग्य आवाजों में शामिल हो गई।

अभिनय की कोई एक परिभाषा नहीं

नाना पाटेकर को केवल गंभीर और आक्रामक भूमिकाओं का अभिनेता मानना उनके साथ न्याय नहीं होगा। उनका अभिनय संसार जितना गंभीर था, उतना ही बहुरंगी भी। अग्निसाक्षी में उन्होंने एक संवेदनशील और जटिल भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। खामोशी : द म्यूजिकल में उनका अभिनय भावनात्मक गहराई का उदाहरण बना। अंगार, तिरंगा, शक्ति : द पावर, अपूर्व चप्पन, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग स्वभाव और मानसिकता वाले किरदार निभाए। अपहरण में नकारात्मक भूमिका ने एक बार फिर साबित किया कि वे किसी भी चरित्र की मनोवैज्ञानिक परतों को अपने अभिनय से उभार सकते थे। और फिर आया वेलकम का उदय शेट्टी। जिस अभिनेता की पहचान गंभीर और तीखे किरदारों से थी, उसने हास्य के क्षेत्र में भी अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उदय शेट्टी स्वयं एक लोकप्रिय सांस्कृतिक चरित्र बन गया। उनकी संवाद-अदायगी, चेहरे के भाव और हास्य की टाइमिंग ने यह सिद्ध कर दिया कि अभिनय की उनकी सीमा किसी एक विधा तक नहीं थी। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अपने समय के दूसरे कलाकारों से अलग करती है।

'नटसम्राट' : मंच, स्मृति और मनुष्य की पीड़ा

यदि नाना पाटेकर के अभिनय जीवन की कुछ सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं को चुना जाए तो मराठी फिल्म नटसम्राट का नाम अवश्य आएगा। इसमें उन्होंने रंगमंच के एक वृद्ध कलाकार की भूमिका निभाई, जो जीवन के उत्तरार्ध में परिवार, स्मृतियों, अकेलेपन और अपनी पहचान के संकट से जूझता है। यह भूमिका उनके अपने रंगमंचीय अनुभव और अभिनय की परिपक्वता का मानो संगम थी। इसमें संवादों की शक्ति के साथ मौन का भी उतना ही महत्व था। एक कलाकार जब अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनी कला और स्मृतियों के सहारे खड़ा रह जाता है, तब उसके भीतर का खालीपन किस तरह आकार लेता है, नाना पाटेकर ने इसे अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत किया। नटसम्राट ने यह भी दिखाया कि अभिनय की असली शक्ति उम्र के साथ कम नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ और गहरी हो सकती है।

पर्दे के पीछे का सैनिक मन

नाना पाटेकर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका भारतीय सैन्य व्यवस्था से जुड़ाव था। वे Territorial Army से जुड़े और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके जीवन में सेना के प्रति सम्मान केवल फिल्मों की भूमिका तक सीमित नहीं रहा। उनका सैनिकों के प्रति लगाव विशेष रूप से कारगिल युद्ध के समय चर्चा में आया। सैनिकों के बीच जाना, उनके जीवन की कठिनाइयों को करीब से समझना और सैन्य जीवन के प्रति सम्मान व्यक्त करना उनके व्यक्तित्व के उस पक्ष को सामने लाता है, जो फिल्मों की चकाचौंध से अलग था। उन्होंने प्रहार : द फाइनल अटैक का निर्देशन भी किया, जिसमें सैनिक जीवन और सैन्य अनुशासन की पृष्ठभूमि थी। निर्देशक के रूप में उनका यह प्रयास बताता है कि सेना और राष्ट्र सेवा के विषय उनके लिए केवल फिल्मी कथानक नहीं थे, बल्कि उनमें उनकी व्यक्तिगत रुचि और संवेदना भी जुड़ी हुई थी।

किसान की पीड़ा तक पहुंचती संवेदना

नाना पाटेकर की मानवीय संवेदना का सबसे ठोस विस्तार उनके सामाजिक कार्यों में दिखाई देता है। महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं, सूखे और ग्रामीण संकट ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। 2015 में उन्होंने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ NAAM Foundation की स्थापना की। संस्था का उद्देश्य महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीण समुदायों की सहायता करना तथा जल संकट और ग्रामीण समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना था। NAAM Foundation के कार्यों में किसानों को सहयोग देने के साथ जल संरक्षण, जल संसाधनों के पुनर्जीवन, गांवों के विकास और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रयास शामिल रहे हैं। संस्था स्वयं अपने आरंभ को महाराष्ट्र के सूखे, किसानों की पीड़ा और बढ़ती किसान आत्महत्याओं के संकट के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित करती है। यहां नाना पाटेकर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। वे केवल किसानों की समस्या पर बोलने वाले कलाकार नहीं रहे; उन्होंने अपनी लोकप्रियता और संसाधनों को उनके बीच काम करने के प्रयास से जोड़ा। इससे उनके सामाजिक सरोकारों को एक व्यावहारिक दिशा मिली।

स्टारडम के बीच सादगी

फिल्मी दुनिया में लोकप्रियता अक्सर व्यक्ति और उसकी सार्वजनिक छवि के बीच दूरी पैदा कर देती है। नाना पाटेकर का व्यक्तित्व इस मामले में अलग दिखाई देता रहा। वे ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उससे पूरी तरह संचालित नहीं हुए। उनकी बातचीत में सीधेपन की छाप थी। उनके विचारों में स्पष्टता थी और कई बार उनकी बेबाकी भी चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तीव्रता, विशिष्ट व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा और स्पष्टवादिता को याद किया है। उनकी सादगी को केवल बाहरी जीवन शैली के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह उनके कला-दर्शन में भी दिखाई देती थी। वे भूमिका को बड़ा बनाने के लिए अनावश्यक अभिनय का सहारा नहीं लेते थे। कई बार उनकी आंखों का एक भाव या आवाज का एक उतार-चढ़ाव पूरे दृश्य पर भारी पड़ जाता था।

आवाज, मौन और अभिनय की भाषा

नाना पाटेकर के अभिनय पर चर्चा उनकी आवाज के बिना अधूरी है। उनकी आवाज में ऐसी प्राकृतिक दृढ़ता थी कि सामान्य वाक्य भी उनके मुंह से निकलकर प्रभावशाली बन जाता था। लेकिन केवल ऊंची या तीखी आवाज उनकी विशेषता नहीं थी। असली शक्ति उनके नियंत्रण में थी। वे जानते थे कि कब आवाज को तेज करना है और कब धीमा। कब शब्दों को रोकना है और कब मौन को संवाद बनने देना है। उनकी आंखें, चेहरे की मांसपेशियां, शरीर का तनाव और संवाद के बीच का विराम सब मिलकर अभिनय की एक ऐसी भाषा बनाते थे.

देश के लिए मेरा दायित्व सबसे अधिक, 25 साल की पूंजी देश के नाम : पीएम मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित किया। यह कार्यक्रम उनके 25 साल की जनसेवा को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जन विश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी हैं। और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।"

उन्होंने कहा, "मैं आप सभी का और सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे सरकार के प्रमुख के तौर पर निरन्तर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह जनता-जनार्दन के लगातार आशीर्वाद का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा, "ये जनता-जनार्दन के निरन्तर आशीर्वाद का परिणाम है। भाजपा, एनडीए, लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं।"

संबोधन के दौरान, पीएम मोदी ने लोकतंत्र और संविधान को भी नमन किया। उन्होंने कहा, "इस दौरान इतने सारे चुनाव हुए। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव, जनता ने हमेशा मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आज भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी वंदन करता हूं। मैं सेवा ज्योति यात्रा में भाग लेने वाले सभी नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता का है। उन्होंने कहा, "आज मैं जो कुछ हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता-जनार्दन का ही है। मेरे लिए जनता-जनार्दन ईश्वर का ही रूप है। लाखों-करोड़ों देशवासियों के विश्वास और लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही, मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही है।" पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने बुधवार सुबह श्री विनायक मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा, "आज प्रातः मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन-रात सेवा कर सकूं।"

अपने 25 साल के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे सिर्फ शुक्रगुजारी महसूस होती है। मैं हर उस व्यक्ति और हर उस अनुभव का आभारी हूं जिसने मुझे कुछ सिखाया। जिन लोगों ने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे विनम्रता सिखाई। जिन लोगों ने मुझे गिराया, उन्होंने मुझे फिर से उठना सिखाया। मेरे समर्थकों ने मेरा हौसला बढ़ाया जबकि मेरे आलोचकों ने मुझे अपने अंदर झांकना सिखाया। जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे भरोसे की ताकत दिखाई।"

मजबूत नींव... बेहतर भविष्य...

सिर्फ घर नहीं आपके सपनों की एक खुशहाल दुनिया का निर्माण...

Plan Build Live Better

Ruchi CONSTRUCTION

आपके सपनों को आकार देने का विश्वास

आज का निवेश कल की सुरक्षित ज़िन्दगी

निर्माण | गुणवत्ता | समयबद्धता | आपकी संतुष्टि हमारी पहचान

निजी भवन निर्माण



- ड्रीम होम
- डुप्लेक्स हाउस
- विला निर्माण
- प्लानिंग एवं 3D डिजाइन
- मजबूत एवं टिकाऊ निर्माण

मकान व दुकान निर्माण



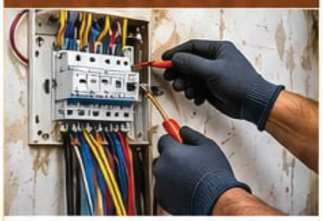
- कमर्शियल कॉम्प्लेक्स
- दुकान / शोरुम
- गोदाम / वेयरहाउस
- रेनोवेशन एवं रिपेयर
- बजट के अनुसार समाधान

ऑफिस व संस्थागत भवन



- ऑफिस भवन
- संस्थागत भवन
- स्कूल / क्लिनिक / हॉस्पिटल
- सरकारी एवं निजी प्रोजेक्ट
- आर्किटेक्चरल सलाह

विद्युत फिटिंग (इलेक्ट्रीकल वर्क)



- घरेलू एवं कमर्शियल फिटिंग
- सुरक्षा मानकों के अनुसार कार्य
- इन्वर्टर/जनरेटर वायरिंग
- सभी प्रकार की विद्युत रिपेयर
- LED लाइटिंग समाधान

अनुभवी टीम | उच्च गुणवत्ता सामग्री | समय पर काम पूरा | उचित दर | ग्राहक संतुष्टि | बिक्री के बाद भी सेवा

नए भवन, मकान, दुकान निर्माण के लिए संपर्क करें

9893162815

(संतोष साहू)

Construction for a Better Tomorrow

विद्युत फिटिंग, लाइट डेकोरेशन के लिए संपर्क करें

9893259555

(कमलेश साहू)

हमारा उद्देश्य
मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य

रुचि कंस्ट्रक्शन
हर निर्माण खास

आपका विश्वास हमारी पहचान

RESIDENTIAL | COMMERCIAL | INSTITUTIONAL | ELECTRICAL | RENOVATION | CONSULTATION

छत्तीसगढ़ शासन

सेवा के 25 वर्ष
सुशासन। गरीब कल्याण। राष्ट्र निर्माण

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

दफ्तरों के चक्कर खत्म



अधिक
जानकारी हेतु
▸ स्कैन करें
या विजिट करें

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400



संवाद आर.ओ./ 14106/ 223